प्रादेशिक समाचार बुलेटिन,
आकाशवाणी, लखनऊ।

प्रसारण तिथि : 11.06.2024 प्रसारण समय : 19:20 बजे

मुख्य समाचार :–

1. केन्द्र ने राज्यों को वित्तीय और आर्थिक विकास में सहायता के लिए एक लाख 39 हजार करोड रुपये से अधिक की कर राशि जारी की : उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक 25 हजार करोड़ रूपये से अधिक मिले।
2. तीसरी बार प्रधानमंत्रो पद की शपथ लेने के बाद नरेन्द्र मोदी अट्ठारह जून को पहली बार आयेंगे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी : किसान सम्मेलन को करेंगे सम्बोधित।
3. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में तबादला नीति समेत 41 प्रस्तावों को किया गया पारित।

और

4. यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों को अगले शैक्षणिक वर्ष से साल में छात्रों को दो बार प्रवेश देने की अनुमति देने का लिया नीतिगत निर्णय।

केंद्र सरकार ने राज्यों को जून महीने के लिए एक लाख उनतालीस हजार करोड़ रुपये से अधिक की कर धनराशि जारी कर दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह राशि राज्य सरकारों को विकास और पूंजी संबंधी व्यय में तेजी लाने में सहायता करेगी। एक रिपोर्ट....

उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक 25 हजार करोड़ रूपये से अधिक, बिहार को 14 हजार करोड़ रूपये से अधिक, मध्य प्रदेश को लगभग 11 हजार करोड़ और पश्चिम बंगाल को 10 हजार पांच सौ करोड़ रुपये से अधिक की राशि मिली है। इस किस्त के साथ ही केंद्र ने 10 जून 2024 तक राज्यों को दो लाख उनासी हजार करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि दे दी है। वर्ष 2024–25 के अंतरिम बजट में राज्यों को करों के हस्तांतरण के लिए लगभग बारह लाख 20 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इसके अतिरिक्त, जून 2024 में धनराशि की एक अतिरिक्त किस्त भी जारी की जाएगी। समाचार कक्ष से विजयलक्ष्मी कासोटिया।

———————————

केंद्र सरकार के ज्यादातर मंत्रियों ने विभाग आवंटन के बाद आज कार्यभार ग्रहण कर लिया। विभाग आवंटन में राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय, अमित शाह को गृह और सहकारिता मंत्रालय, नितिन गडकरी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, निर्मला सीतारमन को वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय तथा डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर को विदेश मंत्री के पद पर बरकरार रखा गया है। पेश है एक रिपोर्ट...

जगत प्रकाश नड्डा नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री बनाए गए हैं। शिवराज सिंह चौहान को कृषि किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय आवंटित किया गया है। राव इंद्रजीत सिंह को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा योजना मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। डॉ. जितेंद्र सिंह को विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय तथा जाधव प्रतापराव गणपतराव को आयुष मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी को कौशल विकास मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है, उन्हें शिक्षा राज्यमंत्री भी बनाया गया है।

सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ, समाचार कक्ष से, मुकेश कुमार बल।

———————

प्रधानमंत्रो पद की तीसरी बार शपथ लेने के बाद श्री नरेन्द्र मोदी अट्ठारह जून को पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जा रहे हैं। अपने एक दिवसीय कार्यक्रम के दौरान वह वाराणसी में किसान सम्मेलन को सम्बोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर कल भाजपा पदाधिकारियों ने पार्टी कार्यालय पर एक बैठक की, जिसमें काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की जानकारी दी। क्षेत्रीय अध्यक्ष ने बताया कि किसान सम्मेलन को सम्बोधित करने के बाद प्रधानमंत्री श्रीकाशी विश्वनाथ का दर्शन–पूजन करेंगे और दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में हिस्सा लेंगे।

———————

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में तबादला नीति समेत 41 प्रस्तावों

को पारित किया गया। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद हुई पहली कैबिनेट बैठक में सभी मंत्री टैबलेट लेकर पहुंचे। मंत्रिपरिषद की बैठक में पारित प्रस्तावों के विषय में जानकारी देते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि स्थानांतरण नीति 2024–25 के तहत समूह क और ख के उन अधिकारियों का स्थानांतरण किया जा सकेगा, जिन्होंने जनपद में 3 वर्ष और मंडल में 7 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। वहीं समूह ग और घ में सबसे पुराने अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाएगा। समूह क और ख के अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए अधिकतम 20 प्रतिशत, वहीं समूह ग और घ के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा रखी गई है। इस स्थानांतरण नीति के तहत सभी स्थानांतरण आगामी 30 जून तक किए जाने हैं। बैठक में बुंदेलखंड के झांसी, महोबा, बांदा, हमीरपुर और मिर्जापुर, सोनभद्र जनपदों में चल रही विभिन्न परियोजनाओं को पूर्ण कराने पर मुहर लगी है। सरकार ने प्रदेश के पांच विश्वविद्यालयों के नामों में भी मामूली संशोधन किया है।

श्री खन्ना ने बताया कि आज जिन प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, उनमें औद्योगिक विकास, आईटी, नगर विकास, गृह विभाग, पीडब्ल्यूडी, कृषि और चिकित्सा विभाग के प्रस्ताव शामिल हैं। इसके अलावा डिफेंस कॉरिडोर नीति का

प्रस्ताव, औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीतियों में बदलाव का प्रस्ताव आज की बैठक में पास हुआ है।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि जिन प्रस्तावों पर आज मुहर लगी है उनमें नोएडा का 500 बेड वाला अस्पताल, आईआईटी कानपुर 500 बेड वाला एमएमटी 750 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा। इसमें केन्द्रीय बजट से स्कूल ऑफ रिसर्च एवं टेक्नोलॉजी के रूप में तैयार किया जाएगा। इसमें राज्य सरकार कानपुर आईआईटी में मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना में 50 करोड़ के अंशदान देगी। वहीं लखीमपुर हवाई अड्डे के विस्तार को स्वीकृत मिली है। इसमें तीन गांवो की जमीन को किसानों से लिया जाएगा। प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को रिटायरमेंट 30 जून और 31 दिसम्बर को हुए है। जिनका एक जुलाई को ग्रेच्युटी लागू है उसे लाभ दिया जाएगा।

————————

ब्रेक

यह समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं।

ताज़ा समाचार जानने के लिये आप हमारी वेबसाइट न्यूज़ ऑन ए0आई0आर0 डॉट जी0ओ0वी0 डॉट आई0एन0 पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक

समाचारों का यह बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं।

प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है।

———————

सर्वोच्च न्यायालय ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा–नीट स्नातक 2024 के बाद मेडिकल कार्यक्रमों में प्रवेश काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने 05 मई को आयोजित नीट परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी– एन टी ए और अन्य से जवाब मांगा है। इस मामले को एक अन्य लंबित याचिका के साथ जोड़कर अब 8 जुलाई को सुनवाई होगी।

———————

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों को अगले शैक्षणिक वर्ष से साल में छात्रों को दो बार प्रवेश देने की अनुमति देने का नीतिगत निर्णय लिया है। वर्तमान में यूजीसी एक वर्ष में एक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश की अनुमति देता हैं। यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने कहा कि इससे उन छात्रों को अधिक फायदा मिलेगा, जिनके बोर्ड परिणामों की घोषणा में देरी हो जाती है या जो स्वास्थ्य समस्याओं या व्यक्तिगत कारणों से प्रवेश लेने से चूक जाते हैं।

———————————

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा देंगे। वह कन्नौज से सांसद के रूप में अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जहां से वह हाल ही में निर्वाचित हुए हैं। वह 2022 के विधानसभा चुनाव में मैनपुरी की करहल सीट से राज्य विधानसभा के लिए चुने गए थे। इटावा जिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा कि बहुत जल्द वह उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष को अपने फैसले से अवगत कराएंगे। इस बीच प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने आज यूपी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। वे विधान परिषद के सदस्य थे। दो दिन पहले ही उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री पद की शपथ ली थी।

———————————

कांग्रेस नेता व सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियका गांधी ने आज रायबरेली पहुंचकर आभार सभा को संबोधित किया। अमेठी और रायबरेली सीट पर जीत के लिए जनता का आभार जताते हुए राहुल गांधी ने कहा कि 2024 के चुनाव में जनता ने हिंसा, झूठ और अहंकार के खिलाफ वोट किया है। भाजपा के लोग संविधान को बदलने की बात कर रहे थे पर जनता ने उन्हें संविधान को माथे से लगाने के लिए मजबूर कर दिया है।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि रायबरेली व अमेठी लोकसभा सीट पर जीत कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत का परिणाम है। इस जीत से साबित हो गया है कि प्रदेश व देश के लोग साफ सुथरी राजनीति चाहते हैं। उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं का भी आभार जताया। इस मौके पर अमेठी से सांसद किशोरी लाल शर्मा भी मौजूद रहे।

———————

देश में नये आपराधिक कानून एक जुलाई से लागू हो जायेंगे। इसके तहत भारतीय न्याय संहिता 2023 ने गैर इरादतन हत्या की एक नई श्रेणी पेश की है, जो न्याय, निवारण और पीड़ितों की सुरक्षा पर जोर देने के साथ मॉब लिंचिंग के मुद्दे को लक्षित करती है। नये आपराधिक कानूनों में धारा 103(2) में प्रस्तुत विशेष प्रावधान में मॉब लिंचिंग से संबंधित अपराधों को संबोधित किया गया ह। इसमें कहा गया है कि जब पांच या अधिक व्यक्तियों का एक समूह मिलकर नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, स्थान, जन्म, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समान आधार पर हत्याएं करता है। ऐसे समूह के प्रत्येक सदस्य को हत्या के लिए सजा के तहत निर्धारित मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा दी जायेगी। साथ ही उचित जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

———————

राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की शादी अनुदान योजना के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदकों की वार्षिक आय सीमा एक लाख रुपये तक बढ़ा दी है। पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण राज्यमंत्री नरेन्द्र कश्यप ने आज बताया कि इस बदलाव से पिछड़े वर्ग के परिवारों को अपनी पुत्रियों की शादी के लिए अधिक सरकारी सहायता प्राप्त करने में मदद मिलेगी। पहले शहरी क्षेत्रों मे आवेदकों की आय सीमा रुपये 56 हजार 460 और ग्रामीण क्षेत्रों में रुपये 46 हजार 80 थी। श्री कश्यप ने आज समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि विभागों के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यक कार्यवाही तत्काल की जाए।

———————————